

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 202]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 1, 2015/चैत्र 11, 1937

No. 202]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 1, 2015/CHAITRA 11, 1937

वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2015

सं. 18/2015 -सीमा-शुल्क

सा.का.नि. 254(अ).-सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना सार्वजिनक हित में आवश्यक है, उन सामग्रियों को, जिनका आयात विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 4.03 की दृष्टि से क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा जारी एक वैध अग्रिम प्राधिकार (एतिशमन पश्चात जिसे उक्त प्राधिकार के रूप में संदर्भित किया गया है) के प्रति भारत में किया गया हो, एतद्वारा, उस पर लगने वाले उस सम्पूर्ण सीमा-शुल्क से जो सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट है और उस सम्पूर्ण अतिरिक्त शुल्क, रक्षोपाय शुल्क, संक्रमणकालीन उत्पाद विशिष्ट रक्षोपाय शुल्क और प्रतिपाटन शुल्क जो कि उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा क्रमश: 3, 8ख, 8ग और 9क के अंतर्गत लगाये गये हैं निम्निलिखित शर्तों के अधीन छूट प्रदान करती है यथा:-

- (i) कि उक्त प्राधिकरण को नामे (डेबिट) के लिए निकासी के वक्त उपयुक्त सीमा-शुल्क अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता;
- (ii) कि उक्त प्राधिकार में निम्नलिखित बातें होनी चाहिए,-
 - (क) आयातक का नाम और पता और समर्थनकारी विनिर्माता का नाम और पता ऐसे मामलों में जहाँ प्राधिकार व्यापारी निर्यातक को जारी किया गया है; और

1512 GI/2015 (1)

- (ख) निर्यात संबंधी दायित्वों को पूरा किये जाने के बाद जहां आयात किया जाता है तो उस स्थिति में परिणामी उत्पाद के निर्यात के शिपिंग बिल के नम्बर और तारीखें और निर्यात का वर्णन, मात्रा और मूल्य; या
- (ग) निर्यात संबंधी दायित्वों को पूरा किये जाने के पहले यदि आयात किया जाता है तो उस स्थिति में आयातित सामग्री का वर्णन और अन्य विशिष्टियां जहां लागू हो और परिणामी उत्पाद के निर्यात का वर्णन, मात्रा और मूल्य;
- (iii) कि आयातित सामग्री, प्राधिकार में उल्लिखित वर्णन तथा अन्य विशिष्टियों जहां लागू हो के अनुरूप हो तथा विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.12 के अनुसार हो और उसका मूल्य और मात्रा भी उक्त प्राधिकार में विनिर्दिष्ट सीमा के भीतर ही हो;
- (iv) कि यदि आयात, निर्यात संबंधी दायित्वों को पूरी तरह निभाने के पहले किया जाता है तो आयातित सामग्री की निकासी के समय आयातकर्ता बंधपत्र उस जमानती या प्रत्याभूति के साथ, उस रूप में तथा उस राशि को भरेगा जो सीमा-शुल्क उपायुक्त या सीमा-शुल्क सहायक आयुक्त, जैसी भी स्थिति हो, विनिर्दिष्ट करें जिसके द्वारा वह, अपने को इस बात से वचनबद्ध करेगा कि वह उस आयातित सामग्री पर लगाये जाने वाले शुल्क इसमें निहित छूट के बिना के बराबर की राशि का भुगतान उक्त सामग्री की निकासी की तारीख से 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज के साथ कहे जाने पर कर देगा जिसके बारे में इस अधिसूचना में वर्णित शर्तों को पूरा नहीं किया गया है;
- (v) कि यदि निर्यात संबंधी दायित्वों को पूरी तरह निभाने के पश्चात् आयात किया जाता है तो उस स्थिति में यदि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 18 (परिणामी उत्पाद के विनिर्माण में प्रयुक्त सामग्री पर भुगतान किये गये शुल्क पर छूट) या नियम 19 के उप-नियम (2) के अंतर्गत दी गई सुविधा या सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के अंतर्गत सेनवेट का लाभ प्राप्त किया जा चुका है तो आयातकर्ता आयातित सामग्री के निकासी के समय उपायुक्त, सीमा-शुल्क या सहायक आयुक्त, सीमा-शुल्क, जैसी भी स्थिति हो, के समक्ष इस आशय का बंधपत्र भरेगा कि आयातित सामग्री का प्रयोग उसके कारखाने में या उसके द्वारा समर्थित विनिर्माता के कारखाने में शुल्क योग्य माल के विनिर्माण में किया जायेगा और वह उक्त सामग्री की निकासी की तारीख से 6 महीने के भीतर क्षेत्राधिकार प्राप्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी या निर्दिष्ट चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट से प्राप्त यह प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर देगा कि आयातित सामग्री का प्रयोग इस रीति से हो गया है:

बशर्ते कि यदि आयातकर्ता आयातित सामग्री पर निहित छूट के बिना लगने योग्य अतिरिक्त सीमा शुल्क का भुगतान करता है, तो आयातित सामग्री की इस शर्त में उल्लिखित बंधपत्र प्रस्तुत किए बिना भी निकासी की जा सकती है और इस प्रकार अदा की गई अतिरिक्त सीमा-शुल्क पर वह सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के अंतर्गत सेनवेट क्रेडिट का लाभ पाने का पात्र होगा;

(vi) कि यदि निर्यात संबंधी दायित्वों को पूरी तरह निभाने के बाद आयात किया जाता है और यदि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 18 (परिणामी उत्पाद के विनिर्माण में प्रयुक्त सामग्री

पर भुगतान किये गये शुल्क पर छूट) या नियम 19 के उप-नियम (2) के अंतर्गत दी गई सुविधा या सेनवेट के ब्रिट नियमावली, 2004 के अंतर्गत सेनवेट का लाभ नहीं लिया है और आयातकर्ता उपायुक्त, सीमा-शुल्क या सहायक आयुक्त, सीमा-शुल्क, जैसी भी स्थिति हो, को उनकी संतुष्टि के अनुसार इस बात का प्रमाण भी सौप देता है तो आयातित सामग्री की शर्त (v) में विनिर्दिष्ट बंधपत्र के बिना भी निकासी की जा सकती है;

(vii) यह कि आयात और निर्यात उन समुद्री बंदरगाहों, विमानपत्तनों अथवा इनलैंड कंटेनर डिपों के माध्यम से अथवा उन भू-सीमा शुल्क स्टेशनों के जिरए से जिनका उल्लेख दिनांक 1 अप्रैल, 2015 की अधिसूचना संख्या 16/2015-सीमा-शुल्क की सारणी 2 में किया गया है अथवा विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 4 के अतर्गत अधिसूचित विशेष आर्थिक जोन के माध्यम से किए जाते हैं:

बशर्ते कि सीमा-शुल्क आयुक्त अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विशेष आदेश द्वारा अथवा सार्वजनिक नोटिस द्वारा और उनके द्वारा यथा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन किसी अन्य समुद्री बंदरगाह, विमानपत्तन, इनलैंड कंटेनर डिपो अथवा भू सीमा-शुल्क स्टेशन के माध्यम से आयात और निर्यात की अनुमित प्रदान कर सकते हैं;

(viii) कि ऐसे परिणामी उत्पादों का निर्यात करके, जो कि भारत में विनिर्मित हो, जो कि उक्त प्राधिकार में विनिर्दिष्ट हो, उक्त प्राधिकार में विनिर्दिष्ट निर्यात संबंधी दायित्वों को (मूल्य और मात्रा दोनों की दृष्टि से) उक्त प्राधिकारण में विनिर्दिष्ट समयाविध के भीतर या ऐसी बढ़ी हुई अविध के भीतर पूरा किया जाय जिसके लिए क्षेत्रीय प्राधिकारी अनुमित प्रदान करें:

बशर्ते कि एडवान्स्ड इन्डरमीडिएट प्राधिकार धारक विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 4.05 (ग) (ii) के अनुसार निर्यातक को परिणामी उत्पादों की आपूर्ति करके निर्यात संबंधी दायित्वों को निभा सकता है:

- (ix) कि आयातकर्ता निर्यात संबंधी दायित्वों के निर्वहन का साक्ष्य उपायुक्त, सीमा-शुल्क या सहायक आयुक्त, सीमा-शुल्क, जैसी भी स्थिति हो, के समक्ष उसकी संतुष्टि के लिये, दायित्वों को पूरा करने की निर्धारित अविध की समाप्ति के साठ दिन के भीतर या ऐसी अविध के भीतर जो उपायुक्त, सीमा-शुल्क या सहायक आयुक्त, सीमा-शुल्क, जैसी भी स्थिति हो, अनुमित प्रदान करें, प्रस्तुत करता है;
- (x) उक्त प्राधिकार हस्तांतरित नहीं किया जायेगा और उक्त सामग्री को न तो हस्तांतरित किया जायेगा और न ही उसकी बिक्री की जायेगी:

बशर्ते कि उक्त सामग्री ऐसे कार्यकर्ता को प्रसंस्करण हेतु हस्तांतरित की जा सकती है जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की उन प्रासंगिक अधिसूचनाओं में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं जो ऐसे कार्य के लिए सामग्री का हस्तांतरण किये जाने की अनुमित देने के लिए जारी किये गए हैं:

बशर्ते और भी कि कोई भी हस्तांतरण जाब वर्क के लिए उन ईकाईयों को नहीं किया जायेगा जो अधिसूचना सं. 32/1999- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 8 जुलाई,1999, 33/1999- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 8 जुलाई, 1999, 39/2001- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 31 जुलाई, 2001, 56/2002-

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 14 नवम्बर, 2002, 57/2002- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 14 नवम्बर, 2002, 49/2003-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 10 जून, 2003, 50/2003-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 10 जून, 2003, 56/2003- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 25 जून, 2003, 71/2003- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 9 सितम्बर, 2003, 8/2004- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 21 जनवरी, 2004 और 20/2007- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 25 अप्रैल, 2007 की दृष्टि से उत्पाद शुल्क लगाये जाने से क्षेत्र आधारित छूट के लिए हकदार है;

- (xi) कि किसी निर्यातक व्यापारी को जारी किये गये उक्त प्राधिकार के संबंध में, इस अधिसूचना के अनुसार आयातकर्ता के लिए जो भी बंधपत्र भरना जरूरी होगा वह निर्यातक व्यापारी और उसको समर्थन देने वाले विनिर्माता द्वारा संयुक्त रूप से भरा जायेगा जो दोनों को संयुक्त रूप से और अलग-अलग बाध्य करेगा कि वे इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करेंगे।
- (2) जहां कि सामग्री दोषपूर्ण या प्रयोग के लिए अनुपयुक्त पायी जाती है वहां उस सामग्री को निकासी की तारीख से छह माह के भीतर या ऐसी बढ़ी हुई अवधि जो और छह माह से अधिक न हो जैसा आयुक्त सीमा-शुल्क अनुमित प्रदान करें विदेशी आपूर्तिकर्त्ता को वापस निर्यात की जा सकती है:

बशर्तें कि ऐसी सामग्री के वापस निर्यात करते समय उपायुक्त सीमा-शुल्क या सहायक आयुक्त सीमा शुल्क, जैसी भी स्थिति हो, की संतुष्टि मे यह पहचान हो कि यह वही सामग्री है जिसका कि आयात किया गया था। स्पष्टीकरण:- इस अधिसूचना के उद्देश्यों के लिए,-

- (I) "शुल्क योग्य माल" से अभिप्राय उस माल से है जिस पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लगता है और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से जिसे छूट प्राप्त नहीं है और जिस पर 'शून्य' दर से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नहीं लगाया जा सकता है।
- (II) "विदेश व्यापार नीति" से अभिप्राय विदेश व्यापर नीति, 2015-2020 से है जिसका प्रकाशन भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने अधिसूचना सं. 01/2015-2020, दिनांक 1 अप्रैल, 2015 समय-समय पर यथा संशोधित, के द्वारा किया है;
- (III) "क्षेत्रीय प्राधिकारी" से अभिप्राय उस विदेश व्यापार महानिदेशक से है जिसकी नियुक्ति विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) की धारा 6 के अंतर्गत की गई है या ऐसे अधिकारी से है जिसे उसके द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकार प्रदान करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो;
- (IV) "विनिर्माण" का वही अभिप्राय है जो विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 9.31 में दिया गया है। (V) "सामग्री" से अभिप्राय निम्न से है,-
 - (क) कच्चे माल, घटक, मध्यवर्ती, उपभोग योग्य, उत्प्रेरक या उस भाग से है जो परिणामी उत्पाद के विनिर्माण के लिए जरूरी होते हैं;
 - (ख) अनिवार्य पुर्जे जो प्राधिकार मूल्य के 10% तक सीमित है और परिणामी उत्पादों के साथ-साथ जिसका निर्यात जरुरी होता है;
 - (ग) परिणामी उत्पाद के विनिर्माण के लिए जरूरी ईधन;
 - (घ) पैकेजिंग सामग्री जो कि परिणामी उत्पादों की पैकेजिंग के लिए जरूरी है;

(VI) "विशिष्ट चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट" से अभिप्राय ऐसे सांविधिक लेखा-परीक्षक या चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट से है जो कम्पनी अधिनियम 2013 (2013 का 18) के अंतर्गत अथवा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अंतर्गत अथवा राज्य सरकार के बिक्री कर या मूल्य संवर्धित कर अधिनियम के अंतर्गत आयातकर्ता के वित्तीय दस्तावेजों को अभिप्रमाणित करता है।

[फा.सं.605/55/2014-डी बी के] संजय कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April, 2015

No. 18/2015-Customs

- G.S.R. 254(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts materials imported into India against a valid Advance Authorisation issued by the Regional Authority in terms of paragraph 4.03 of the Foreign Trade Policy (hereinafter referred to as the said authorisation) from the whole of the duty of customs leviable thereon which is specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) and from the whole of the additional duty, safeguard duty, transitional product specific safeguard duty and anti-dumping duty leviable thereon, respectively, under sections 3, 8B, 8C and 9A of the said Customs Tariff Act, subject to the following conditions, namely:-
 - (i) that the said authorisation is produced before the proper officer of customs at the time of clearance for debit;
 - (ii) that the said authorisation bears,-
 - (a) the name and address of the importer and the supporting manufacturer in cases where the authorisation has been issued to a merchant exporter; and
 - (b) the shipping bill number(s) and date(s) and description, quantity and value of exports of the resultant product in cases where import takes place after fulfillment of export obligation; or
 - (c) the description and other specifications where applicable of the imported materials and the description, quantity and value of exports of the resultant product in cases where import takes place before fulfillment of export obligation;
 - (iii) that the materials imported correspond to the description and other specifications where applicable mentioned in the authorisation and are in terms of para 4.12 of the Foreign Trade Policy and the value and quantity thereof are within the limits specified in the said authorisation;
 - (iv) that in respect of imports made before the discharge of export obligation in full, the importer at the time of clearance of the imported materials executes a bond with such surety or security and in such form and for such sum as may be specified by the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, binding himself to pay on demand an amount equal to the duty leviable, but for the exemption contained herein, on the imported materials in respect of which the conditions specified in this notification are not complied with, together with interest at the rate of fifteen percent per annum from the date of clearance of the said materials;
 - (v) that in respect of imports made after the discharge of export obligation in full, if facility under rule 18 (rebate of duty paid on materials used in the manufacture of resultant product) or sub-rule (2) of rule 19 of the Central Excise Rules, 2002 or of CENVAT Credit under CENVAT Credit Rules, 2004 has been availed, then the importer shall, at the time of clearance of the imported materials furnish a bond to the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, binding himself, to use the imported materials in his factory or in the factory of his supporting manufacturer for the manufacture of dutiable goods and to submit a certificate, from the jurisdictional Central Excise Officer or from a specified chartered

accountant within six months from the date of clearance of the said materials, that the imported materials have been so used:

Provided that if the importer pays additional duty of customs leviable on the imported materials but for the exemption contained herein, then the imported materials may be cleared without furnishing a bond specified in this condition and the additional duty of customs so paid shall be eligible for availing CENVAT Credit under the CENVAT Credit Rules, 2004;

- (vi) that in respect of imports made after the discharge of export obligation in full, and if facility under rule 18 (rebate of duty paid on materials used in the manufacture of resultant product) or sub-rule (2) of rule 19 of the Central Excise Rules, 2002 or of CENVAT credit under CENVAT Credit Rules, 2004 has not been availed and the importer furnishes proof to this effect to the satisfaction of the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs as the case may be, then the imported materials may be cleared without furnishing a bond specified in condition (v);
- (vii) that the imports and exports are undertaken through the seaports, airports or through the inland container depots or through the land customs stations as mentioned in the Table 2 annexed to the Notification No.16/2015- Customs dated 01.04.2015 or a Special Economic Zone notified under section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005):

Provided that the Commissioner of Customs may, by special order or a public notice and subject to such conditions as may be specified by him, permit import and export through any other sea-port, airport, inland container depot or through a land customs station within his jurisdiction;

(viii) that the export obligation as specified in the said authorisation (both in value and quantity terms) is discharged within the period specified in the said authorisation or within such extended period as may be granted by the Regional Authority by exporting resultant products, manufactured in India which are specified in the said authorisation:

Provided that an Advance Intermediate authorisation holder shall discharge export obligation by supplying the resultant products to exporter in terms of paragraph 4.05 (c) (ii) of the Foreign Trade Policy;

- (ix) that the importer produces evidence of discharge of export obligation to the satisfaction of the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, within a period of sixty days of the expiry of period allowed for fulfillment of export obligation, or within such extended period as the said Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, may allow;
- (x) that the said authorisation shall not be transferred and the said materials shall not be transferred or sold;

Provided that the said materials may be transferred to a job worker for processing subject to complying with the conditions specified in the relevant Central Excise notifications permitting transfer of materials for job work;

Provided further that, no such transfer for purposes of job work shall be effected to the units located in areas eligible for area based exemptions from the levy of excise duty in terms of notification Nos. 32/1999-Central Excise dated 08.07.1999, 39/2001- Central Excise dated 31.07.2001, 56/2002- Central Excise dated 14.11.2002, 57/2002- Central Excise dated 14.11.2002, 49/2003-Central Excise dated 10.06.2003, 50/2003- Central Excise dated 10.06.2003, 56/2003- Central Excise dated 25.06.2003, 71/03- Central Excise dated 09.09.2003, 8/2004- Central Excise dated 21.01.2004 and 20/2007-Central Excise dated 25.04.2007;

- (xi) that in relation to the said authorisation issued to a merchant exporter, any bond required to be executed by the importer in terms of this notification shall be executed jointly by the merchant exporter and the supporting manufacturer binding themselves jointly and severally to comply with the conditions specified in this notification.
- 2. Where the materials are found defective or unfit for use, the said materials may be re-exported back to the foreign supplier within six months from the date of clearance of the said material or such extended period not exceeding a further period of six months as the Commissioner of Customs may allow:

Provided that at the time of re-export the materials are identified to the satisfaction of the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, as the materials which were imported.

Explanation, - For the purposes of this notification,-

- (I) "Dutiable goods" means excisable goods which are not exempt from central excise duty and which are not chargeable to 'nil' rate of central excise duty;
- (II) "Foreign Trade Policy" means the Foreign Trade Policy, 2015-2020, published by the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry vide notification No. 01/2015-2020, dated the 1st April, 2015 as amended from time to time;
- (III) "Regional Authority" means the Director General of Foreign Trade appointed under section 6 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992) or an officer authorized by him to grant an authorisation under the said Act;
- (IV) "Manufacture" has the same meaning as assigned to it in paragraph 9.31 of the Foreign Trade Policy;
- (V) "Materials" means,-
 - (a) raw materials, components, intermediates, consumables, catalysts and parts which are required for manufacture of resultant product;
 - (b) mandatory spares within a value limit of ten per cent of the value of the authorisation which are required to be exported along with the resultant product;
 - (c) fuel required for manufacture of resultant product;
 - (d) packaging materials required for packing of resultant product;
- (VI) "Specified Chartered Accountant" means a statutory auditor or a Chartered Accountant who certifies the importer's financial records under the Companies Act, 2013 (18 of 2013) or the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Sales Tax or the Value Added Tax Act of the State Government.

[F. No. 605/55/2014-DBK]

SANJAY KUMAR, Under Secy.